



युनाइटेड किंगडम में कैपरकेली पक्षी विलुप्त के कारण पर हैं। एक नए डेटा के अनुसार स्कॉटलैंड में इस प्रजाति के सिर्फ 542 पक्षी ही बचे हैं। छह साल पहले हुए सर्बे के बाद से अब तक इस प्रजाति के पक्षियों की संख्या में 50 प्रतिशत कमी आ चुकी है, जो बहुत चिन्ताजनक है। वैज्ञानिकों का कहना है कि, कई कारण हैं जिनकी सरवाइवल रेट और प्रजनन की सफलता की दर घटी है। इनमें प्रमुख हैं, बसंत के मौसम में बारिश होना, जिससे प्रजनन से पहले मादा की फिटनेस पर असर पड़ा है और बच्चों के जीवित रहने की क्षमता कम हो गई है। इसके अलावा परभक्षी व विखंडित प्राकृतिक आवास भी एक बड़ी समस्या है। विशेषज्ञों ने विभिन्न संस्थाओं से इन पक्षियों की मदद के लिए एकजुट होकर काम करने की अपील की है। रॉयल सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स की स्कॉटलैंड शाखा के संरक्षण वैज्ञानिक, निक विलकिन्सन ने कहा कि, कैपरकेली की संख्या का यह नवीनतम अनुमान बताता है कि स्कॉटलैंड में इनकी स्थिति कितनी गंभीर है। पूर्व सर्वेक्षणों में इनकी संख्या 1000 से 2000 के बीच रहती थी लेकिन पिछली सर्वेक्षणों के आंकड़ों के अनुसार मात्र 542 कैपरकेली विद्यमान बची हैं, यह स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। देश में कैपरकेली का हर 6 वर्ष में सर्वे किया जाता है। हालिया छठा सर्वे 2021-22 की सर्वेक्षणों में किया गया था। इससे पहले नेचरस्कॉट साइंटिफिक एडवायज़री कमेटी ने फरवरी में एक शोध प्रकाशित किया था, जिसमें चेतावनी दी गई थी कि, अगर आबादी में कमी आने का यही रुझान जारी रहा, तो दो-तीन दशक में ये पक्षी यू.के. में फिर से लुप्त हो जायेगा। यू.के. में सिर्फ स्कॉटलैंड में ही कैपरकेली पक्षी पाए जाते हैं, खासकर यहां के शंकु वनों में। ये शमीले पक्षी अक्सर पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बैठे होते हैं और जंगल में छुपे रहते हैं। माना जाता है कि, स्कॉटलैंड में कैपरकेली की कुल आबादी का 85 प्रतिशत भाग कैर्नगर्म्स नेशनल पार्क में रहता है।

लालू यादव की तबीयत क्रिटिकल

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व आर.जे.डी. सुप्रिमो लालू प्रसाद यादव की स्थिति चिन्ताजनक बनी हुई है। किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उनकी स्थिति सामान्य नहीं है। अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। वैसे लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य अब पूरी तरह स्वस्थ हैं।

लालू यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य ने कहा कि, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद भी उनकी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है।

हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गयी है। अस्पताल से घर आने के बाद रोहिणी आचार्य ने सोमवार को ट्वीट किया कि आज मैं आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गयी, मगर पापा अभी भी हॉस्पिटल में हैं। उनकी तबीयत कुछ नासाज बनी हुई है। बस आप लोगों की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

बेनीवाल ने लोकसभा में अग्निपथ का विरोध किया

जालू खंबाता-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। राजस्थान की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता एवं नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने सशस्त्र सेनाओं में चार वर्ष का रोजगार उपलब्ध करवाने वाली अग्निपथ स्कीम को वापस लेने का सोमवार को लोकसभा में अनुरोध

नागौर से सांसद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने कहा कि, अग्निपथ योजना से युवाओं का भविष्य अधकारमय हो जाएगा।

किया। प्रश्नकाल के दौरान इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्कीम ना तो देश सेवा की इच्छा रखने वाले युवाओं के हित में है और ना ही सेना के। उन्होंने इच्छा जतायी इस स्कीम के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक और "सन राइज" हुआ तमिलनाडु में

मु.मंत्री स्टालिन के पुत्र उदयानिधि को कैबिनेट मंत्री बनाया

लक्ष्मण वेंकट कुची-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेम कडगम (द्रमुक) जो संदेव ही उत्तराधिकार की योजना तैयार करती रही है, ने पार्टी की राजगद्दी के लिये राजनैतिक उत्तराधिकारी को तैयार करने की घोषणा कर दी है। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुये मुख्यमंत्री तथा पार्टी प्रमुख एम.के. स्टालिन के पु. उदयानिधि स्टालिन राज्य मंत्रिमण्डल में शामिल किया जा रहे हैं।

भाजपा पहले से ही द्रमुक (डी.एम.के.) को एक परिवार की पार्टी बताई आई है। उदयानिधि को मंत्री बनाये जाने से भाजपा सत्तारूढ़ दल पर हमला बोलने का एक और हथियार मिल जायेगा। इसके बावजूद, द्रमुक उदयानिधि स्टालिन को अगले नेता के रूप में

उदयानिधि को यूथ व स्पोर्ट्स विभाग की जिम्मेवारी दी जायेगी सरकार में

2019 में उदयानिधि को डीएमके की यूथ विंग की जिम्मेवारी दी गयी थी। तथा अब लगभग तीन साल में कैबिनेट मंत्री बनाकर स्टालिन का उत्तराधिकारी होने की घोषणा सी की गयी है।

स्टालिन भी यूथ विंग के नेता होने के बावजूद 1982 से 2017 तक पिता करुणानिधि के अधीन एक तरह से "इन्टर्नशिप" कर रहे थे तथा 2017 में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे।

उदयानिधि फिल्म अभिनेता भी हैं तथा कुछ फिल्मों प्रोड्यूसर व निर्देशक के रूप में भी बना चुके हैं।

प्रोजेक्ट करने जा रही है तथा उसे पार्टी सेटअप में समायोजित करने के कदम उठा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार,

उदयानिधि को बुधवार को तमिलनाडु के मंत्रिमण्डल में शामिल किया जाएगा। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी "मॉरल अथॉरिटी" (नैतिक अधिकार) बढ़ा रहे हैं पार्टी में ?

इस मॉरल अथॉरिटी का असर राजस्थान में नेतृत्व की समस्या सुलझाने में भी मदद करेगा

डॉ. सतीश मिश्रा-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। हिमाचल प्रदेश के छः बार मुख्यमंत्री रहे राजा वीरभद्र सिंह की विधवा तथा पार्टी की प्रांतीय अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह को जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने श्रद्धा एवं आत्मीयतापूर्वक गले लगाया, तो लोग सहज एवं स्वाभाविक रूप से करतल ध्वनि किये बिना नहीं रह सके। राहुल की स्नेह एवं श्रद्धामिश्रित भंगिमा तथा लोगों द्वारा की गई स्वप्रेरित करतल ध्वनि देश की इस सबसे पुरानी पार्टी में जन्म ले रहे नये समीकरणों का संकेत साफ दिखाई दे रहा था।

कल शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह को

बारीकी से देखने से एक ऐसी छोटी सी खिड़की खुलती दिखाई दी, जिसमें से यह दिखाई दे रहा था कि राहुल गांधी किस तरह से गुटबाजी से पीड़ित पार्टी को एक करने वाले तत्व के रूप में उभर रहे हैं।

इस बात को पूरी तरह समझते हुये कि अहं को तुष्ट करते हुये, उसे अपने अनुकूल बनाना जरूरी होता है, राहुल गांधी तुरंत ही उस महिला के सम्मान में अपनी कुर्सी से खड़े हो गये थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिये अपनी दावेदारी पुरजोर तरीके से पेश की थी तथा मुख्यमंत्री नहीं बनाये जाने की स्थिति में, अभी-अभी हुये विधानसभा चुनावों में हुई पार्टी की जीत के जश्न के रंग में भंग डालने की धमकी तक दे दी थी।

राहुल गांधी ने शिमला में शपथ ग्रहण समारोह में जिस आत्मीयता से स्वः वीरभद्र सिंह की पत्नी को अपनी कुर्सी से तत्परता से उठकर गले लगाया, इस बात का प्रमाण था कि, नेताओं के अहम को सहलाना जरूरी है, अगर पार्टी को बिना व्यवधान के चलाना है।

राहुल ने सुक्खू की माँ और दो पुत्रियों को मंच पर प्रतिभा सिंह के बगल में बिठाया और इस कृत्य को जनता से जितनी सराहना व तालियां मिलीं, उससे यह साबित हुआ कि जनता भी "मॉरल अथॉरिटी" के इस इजहार से प्रसन्न है।

इतिहास भी यह बताता है कि "मॉरल अथॉरिटी" के अभाव में पोलिटिकल पार्टी फेल हो जाती हैं, धीरे-धीरे। तथा राजनीतिक दलों को सफलता मिलती है अगर पार्टी में एक स्वस्थ परम्परा हो जिसमें परिश्रमी व बहादुरों को पार्टी सम्मानित करती है।

7 सितम्बर को कन्याकुमारी से शुरु हुई भारत जोड़ो यात्रा, जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश को पार करने के बाद इस समय राजस्थान में है, के

बीच के पड़ाव के समय किया गया मूल्यांकन बताता है कि कांग्रेस के अंदर और उसके बाहर राहुल गांधी की स्वीकार्यता बढ़ रही है तथा उनकी जो छवि जनमानस में थी, वह बदल रही है।

एक टी.वी. समाचार चैनल को दिया गया राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का हाल ही का एक इन्टरव्यू इस बात का एक और संकेत है कि पार्टी में राहुल गांधी का कद बढ़ रहा

एल.ए.सी पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच भारी झड़प

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। भारत और चीनी सैनिकों के बीच तवांग सेक्टर में झड़प की खबर आ रही है। 3 दिन पहले 9 दिसंबर को दोनों देशों के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई। भारतीय

गत 9 दिसम्बर को चीन के 300 सैनिकों ने पत्थरबाजी करते हुये भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की कोशिश की, भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिसमें चीन के करीब 20 सैनिक और भारत के 8 सैनिक गम्भीर रूप से घायल हुये हैं।

सैनिकों ने चीनी सैनिकों को करारा जवाब दिया। हिंसक झड़प में दोनों देशों के सैनिक जखमी हुए हैं। झड़प के बाद भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रिटायर्ड जजों की एडहॉक नियुक्ति का प्रस्ताव अस्वीकार

सरकार का तर्क है कि इस नियुक्ति के लिए भी वह पूरी प्रक्रिया होगी, जो जजों की नियुक्ति के लिए सामान्य तौर पर लागू होती है

जालू खंबाता-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। सरकार ने दो या तीन वर्षों के लिये तदर्थ (एड हॉक) आधार पर सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त किये जाने की कोशिश को एक बार पुनः खारिज कर दिया है तथा कहा है कि इस प्रक्रिया की गहराई तक जाना जरूरी है, जो नियमित जजों की नियुक्ति के लिये की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह जानने के लिये 8 फरवरी की सुनवाई नियत की है कि क्या नियमित रिक्त स्थानों को भरने के लिये अनुच्छेद 224-ए का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि बम्बई, इलाहाबाद तथा पटना सहित, कई उच्च न्यायालयों में जजों के 50 प्रतिशत से ज्यादा पद रिक्त हैं। लेकिन सरकार एड हॉक जजों को नियुक्त किये जाने के मामले में अपनी अनिच्छा प्रेषित कर दी है।

यह विचार सबसे पहले तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एस.एच. कपाड़िया ने संविधान के अनुच्छेद 224-ए के तहत केन्द्र को लिखे पत्र में व्यक्त किया था, क्योंकि जजों के पदों को भरने के लिये बेहतर जजों की उपलब्धता उनकी जानकारी में आई थी। लेकिन उन्होंने इस

एडहॉक नियुक्ति के लिए भी नाम कोलीजियम द्वारा प्रस्तावित होने चाहिए तथा सरकार को स्वीकार्य होने चाहिए।

रिटायर्ड जजों की एडहॉक नियुक्ति का यह प्रश्न इस समय इसलिए उठा क्योंकि, हाईकोर्टों में अभी भी 50 प्रतिशत स्थान रिक्त पड़े हैं।

यह प्रस्ताव पहले 2010-11 में भी आया था, मुख्य न्यायाधीश कपाड़िया की ओर से। न्यायाधीश का तर्क था, नये अच्छे जज की उपलब्धि बहुत कम है, अतः रिक्त पदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है।

सरकार ने उस समय भी यह आपत्ति की थी प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए कि, क्या मापदण्ड अपनाये जायेंगे रिटायर्ड जज का नाम पुनः नियुक्ति की सिफारिश करते समय तथा कौन और कैसे निर्णय लेगा कि, पुनः नियुक्ति के लिए जज स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट है।

तीसरी आपत्ति थी कि, दुराचरण (मिसकन्डक्ट) की शिकायत पर एडहॉक जजों को बर्खास्त करने की क्या प्रक्रिया होगी।

विचार को उस समय त्याग दिया था, जब सरकार ने कहा था कि इसके लिये भी वही प्रक्रिया जरूरी होगी- उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नामों की सिफारिश करेंगे, तथा जॉच-पड़ताल के बाद, सर्वोच्च न्यायालय की कोलीजियम अपनी मंजूरी के साथ उन्हें सरकार के पास भेजेंगी तथा सरकार उन्हें नियुक्ति प्रदान करेगी। सरकार ने दुराचरण के मामले में एड-हॉक जजों

को हटाये जाने के संबंध में इस प्रक्रिया में दोष निकाला। इस योजना के अन्तर्गत वे नियम तथा शर्तें भी तय नहीं की जा सकीं जिनके आधार पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नामों की सिफारिश करेंगे और न इस मामले में ही स्पष्टता थी कि यह कैसे तय होगा कि सेवानिवृत्त जज फिट हैं अथवा नहीं।

एड-हॉक जजों की नियुक्ति अब तक तीन बार हुई है। सबसे पहले, मध्य

प्रदेश उच्च न्यायालय में 1972 में, दूसरी बार मद्रास उच्च न्यायालय में तथा अन्त में, 2007 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। 2021 में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अनुच्छेद 224-ए के तहत एड-हॉक नियुक्तियों तभी संभव हैं, जब 20 प्रतिशत रिक्तियाँ भरी नहीं गई हों तथा 10 प्रतिशत मामलों को लम्बित हुये 5 साल से अधिक समय हो गया हो।

चक्रवात के बाद आंध्रप्रदेश में सोना ढूँढने वालों का तांता लगा

यह परंपरा व किवंदती पुरानी है कि, चक्रवात के बाद स्वर्ण आभूषण समुद्र तट पर बिखरे हुए मिलते हैं, जिसे स्थानीय मछुआरे परिवार ढूँढने में जुट जाते हैं

लक्ष्मण वेंकट कुची-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। काकोनाडा के पास उप्पडा मण्डल के तटवर्ती गांवों में रहने वाले मछुआरे प्रायः चक्रवातों का स्वागत करते हैं और उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं। मछली पकड़ने के काम में लगे कई स्त्री-पुरुष चक्रवाती तूफान "मैडूस" को लेकर प्रशासन की चेतावनियों की अनदेखी कर शनिवार को समुद्र की ओर चले गए थे सभी लोग "सोने" की तलाश में थे। हाथ से बनने वाली कौटन साड़ियों के लिए मशहूर उप्पडा मण्डल के 16 गांवों के कई सौ मछुआरे 2 किमी लम्बे सी-बीच पर मौजूद हैं। इन्हें चक्रवातों के दौरान समुद्र तट पर बहकर आने वाले सोने के छोटे-छोटे टुकड़ों की तलाश है। पिछले चार दशक या अधिक समय से आसपास के गांवों में चर्चा है कि

किवंदती है कि, समुद्र तट पर स्थित मंदिर कालान्तर में समुद्र में समा जाते हैं तथा जब "सायक्लोन" (चक्रवात) से समुद्र में उथल पुथल होती है तो इन मंदिरों को अर्पित स्वर्णाभूषण तट पर आ जाते हैं।

स्वर्णाभूषणों के छोटे-छोटे टुकड़े इस सी-बीच पर बहकर आते हैं। दन्तकथा यह है कि करीब 40 वर्ष पूर्व तक जबदस्त चक्रवाती तूफान में पास का एक मंदिर डूब गया था और यह माना जाता है कि मंदिर में रखे सोने के छोटे-छोटे कई टुकड़े हो गए और समुद्र के पैदे में जाकर जम गए। चक्रवाती तूफान की लहरों से समुद्र तट में मंथन होता है और सोने के ये टुकड़े ऊपर आकर सी-बीच पर जमा हो जाते हैं। चेन्नई, तमिलनाडु और आंध्र-प्रदेश के हिस्सों को प्रभावित करने वाला चक्रवात मैडूस अपने आप में अलग

नहीं है। इसमें मछुआरों का हुजूम सोने की तलाश में उप्पडा के सी-बीच पर जमा हो गया।

सोना पाने की इस आपाधापी को पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे एवं स्थानीय मीडिया के एक कर्मी जी. केसावुडू ने बताया कि सोना तलाशने के काम में लोग सुबह 6 बजे से लग जाते हैं और यह काम सांझ ढलने तक चलता है। उन्होंने बताया कि समुद्र पर मिलने वाली चीजों के बारे में मछुआरे प्रायः मौन रहते हैं वे इन चीजों को गलाते हैं और बेच देते हैं, लेकिन प्रशासन उनके (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

पत्रकारों को रेल किराये में छूट

जालू खंबाता-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-नई दिल्ली, 12 दिसम्बर। मावल में शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पाबावें ने सोमवार को लोकसभा में अनुरोध किया कि अधिस्वीकृत पत्रकारों को लम्बी दूरी और एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा के लिए किराए में प्रदत्त 50 प्रतिशत छूट को फिर से बहाल किया जाए। उन्होंने लोकसभा

शिवसेना सांसद श्रीरंग अप्पा ने लोकसभा में कहा कि, कोविड में पत्रकारों की 50 प्रतिशत किराया छूट वापस ले ली गयी थी, जिसे बहाल किया जाए।

में एक विशेष उल्लेख में कहा कि कोविड-19 अवधि में यह छूट वापस ले ली गई थी, जबकि अब स्थिति सामान्य हो चुकी है और सभी ट्रेने यथावत संचालित हो रही हैं, लेकिन पत्रकार उक्त पुविधा से वंचित है।